



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2000/वैशाख 14, 1922

No. 249]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2000/VAISAKHA 14, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा.का.नि. 379(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (ड्राफ्ट, चैक, लिखत का भुनाना और ब्याज का मंदाय) नियम, 2000 है।

(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) “न्याय निर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) “प्राधिकृत व्यक्ति” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(घ) “चैक” के अंतर्गत यात्री चैक भी है;

(ङ) “अन्वेषण” से अधिनियम की धारा 37 के अधीन परिकल्पित अन्वेषण अभिप्रेत है;

(च) “विशेष निदेशक (अपील)” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक (अपील) अभिप्रेत है;

(छ) “अपील अधिकरण” से अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण अभिप्रेत है।

3. **ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत का भुनाए जाने के लिए परिदान :—**जहां धारा 37 में निर्दिष्ट अन्वेषण, अधिनियम या किसी नियम, विनियम, निदेश या आदेश के किसी उपबंध के अभिकथित उल्लंघन के लिए या किसी ऐसी शर्त के अतिक्रमण के लिए जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकार प्रदान किया है, किया जाता है और कोई ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत जो ऐसे अन्वेषण के लिए सुसंगत है, वहां ऐसा अधिकारी ऐसे ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत को भारतीय रिजर्व बैंक को या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को जिसे अधिकारी विनिर्दिष्ट करें भुनाने के लिए परिदत्त करवाएगा।

4. **ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत का भुनाया जाना :—**भारतीय रिजर्व बैंक या कोई प्राधिकृत व्यक्ति ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत को भुनाने के लिए अविलंब कार्रवाई करेगा और इस प्रकार भुनाए जाने पर, वसूल किए गए आगमों को (ऐसे भुनाने के लिए उपगत कमीशन और व्यय को कटकर) प्रवर्तन निदेशालय के नाम पृथक खाते में जमा करेगा।

5. **खाता खोला जाना :—**जहां अधिनियम की धारा 37 में निर्दिष्ट कोई अन्वेषण, अधिनियम या किसी नियम, विनियम या निदेश या आदेश के किसी उपबंध के अभिकथित उल्लंघन या किसी ऐसी शर्त के अतिक्रमण के लिए जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकार देता है, किया जा रहा है और ऐसे अन्वेषण से सुसंगत भारतीय करेंसी प्रवर्तन निदेशालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में है तब ऐसा अधिकारी ऐसी भारतीय करेंसी को प्रवर्तन निदेशालय के नाम में पृथक खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करेगा।

6. **क्षतिपूर्ति :—**केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे दायित्व के प्रति जो भारतीय रिजर्व बैंक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत के भुनाए जाने के कारण या उसके संबंध में उठाने पड़े हों, भारतीय रिजर्व बैंक या प्राधिकृत व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करेगी।

7. **आगमों के संदाय के लिए निदेश :—**(i) जहां अन्वेषण या न्याय निर्णयन के दौरान यह पाया जाता है कि कोई ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत ऐसे अन्वेषण के लिए सुसंगत नहीं है वहां, यथास्थिति अन्वेषण अधिकारी या न्याय निर्णायक प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित करेगा कि ऐसे ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत के आगमों का संदाय किस व्यक्ति को किया जाए।

(ii) जहां, यथास्थिति, विशेष निदेशक (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के दौरान यह पाया जाता है कि कोई ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखत ऐसी अपील के लिए सुसंगत नहीं समझी गई है तो, यथास्थिति, विशेष निदेशक (अपील) या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश पारित करेगा जिसे ड्राफ्ट, चैक या अन्य लिखतों के आगमों का संदाय किया जाए।

8. **अभिगृहीत भारतीय करेंसी पर ब्याज का संदाय :—**(i) जहां अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 37 के अधीन अभिगृहीत भारतीय करेंसी उल्लंघन में अंतर्बलित नहीं है और इसे वापिस करना होगा, वहां यह ऐसे व्यक्तियों को, अभिगृहण की तारीख से संदाय की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ, वापस की जाएगी।

(ii) जहां न्यायनिर्णयन के दौरान यह पाया जाता है कि अभिगृहीत भारतीय करेंसी ऐसे न्यायनिर्णयन के लिए सुसंगत नहीं है, वहां न्याय निर्णायक प्राधिकारी, ऐसी भारतीय करेंसी 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ ऐसे व्यक्ति को वापस करने का, आदेश पारित कर सकेगा।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

राम सेवक शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2000

G.S.R. 379(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Encashment of Draft, Cheque, Instrument and payment of interest) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 2000

2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires;-

- (a) "Act" means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (b) "Adjudicating Authority" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 16 of the Act;
- (c) "Authorised Person" means a person as defined in clause (c) of section 2 of the Act;
- (d) "Cheque" includes a traveller's cheque;
- (e) "Investigation" means an investigation as envisaged under section 37 of the Act;
- (f) "Special Director (Appeals)" means Special Director (Appeals) appointed by the Central Govt. under sub-section (1) of section 17 of the Act;
- (g) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal for Foreign Exchange established under section 18 of the Act.

3. Delivery of Draft, Cheque and other Instrument for Encashment

Where investigation referred to in section 37 is being taken up into any alleged contravention of any provision of the Act or of any rule, regulation, direction or order, or violation of any condition subject to which Reserve Bank of India gives authorisation, made thereunder, and any draft, cheque or other instrument relevant for such investigation such officer shall cause such draft, cheque or other instrument to be delivered for encashment to Reserve Bank of India or an authorised person as the officer may specify.

- 4. **Encashment of draft, cheque or other instrument** - The Reserve Bank of India or an authorised person shall take steps without delay for encashing the draft, cheque or other instrument and, on such encashment, shall credit the proceeds realised (less any commission and expenses incurred for such encashment) to a separate account in the name of the Directorate of Enforcement.
- 5. **Opening an Account :-** Where Investigation referred to in section 37 of the Act is being taken up into any alleged contravention of any provision of the Act or any rule, regulation or direction or order, or violation of any condition subject to which Reserve Bank of India gives authorisation, the indian currency relevant to such investigation is in the custody of an officer of Enforcement Directorate, then, such officer shall deposit the indian currency in a nationalised bank to a separate account in the name of Directorate of Enforcement.
- 6. **Indemnity:-** The Central Government shall indemnify the Reserve Bank of India or an authorised person against any liability which the Reserve Bank of India or an authorised person may incur by reason of, or in connection with, the encashment of the draft, cheque or other instrument delivered to it.

7. **Direction for Payment of the Proceeds :-** (i) Where it has been found during the course of investigation or adjudication that, any draft, cheque or other instrument is not relevant for such investigation, the Investigating Officer or the Adjudicating Authority, as the case may be, pass such order that the person to whom the proceeds of such draft, cheque or other instrument may be paid.
- (ii) Where it has been found during the course of appeal before the Special Director (Appeals) or the Appellate Tribunal or the High Court, as the case may be, that, any draft, cheque or other instrument is not considered relevant for such appeal, then, the Special Director (Appeals) or the Appellate Tribunal or the High Court, as the case may be, pass such order specifying the person to whom the proceeds of the draft, cheque or other instruments may be paid.
8. **Payment of interest on the seized Indian currency:-** (i) Where it is found after completion of the investigation that the Indian currency seized under section 37 of the Act is not involved in the contravention and is to be returned, the same shall be returned to such persons together with interest at the rate of 6% per annum from the date of seizure till the date of payment.
- (ii) Where it has been found during the course of adjudication that the seized Indian currency is not relevant for such adjudication, the Adjudicating Authority may pass such order returning such Indian currency togetherwith interest at the rate of 6% per annum to such person.

[F. No. 1/9/EC/97]

R. S. SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा. का. नि. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 39 के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दस्तावेजों के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा (दस्तावेज अधिप्रमाणन) नियम, 2000 है।
(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे।
2. अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकारी और दस्तावेजों के अधिप्रमाणन की रीति :—भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त कोई ऐसा दस्तावेज, जिस पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 3 द्वारा कोई नोटरी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मुद्रा लगाई गई और हस्ताक्षर किए गए तात्पर्यित है, अधिनियम की धारा 39 के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित माना जाएगा।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

राम सेवक शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2000

G. S. R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 read with the section 39 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules to govern the procedure of authentication of documents, namely :—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange (Authentication of Documents) Rules, 2000.
(2) They shall come into force on 1st day of June, 2000
2. Authority for authentication and the manner of authentication of documents.—Any document received from any place outside India purporting to have affixed, impressed or submitted thereon or thereto the seal and signature of any person who is authorised by section 3 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) to do any notarial acts shall be deemed duly authenticated for the purpose of section 39 of the Act.

[F. No. 1/9/EC/97]

R. S. SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा.का.नि. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोकहित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 है;
(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) “अधिनियम” से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;
(ख) “आहरण” से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत प्रत्यय पत्र लेना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या ए टी एम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी सम्मिलित है ;
(ग) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिषेध :—किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण प्रतिषिद्ध है, अर्थात् :—

- (क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार; या
- (ख) नेपाल और/या भुटान में यात्रा; या
- (ग) नेपाल या भुटान के निवासी व्यक्ति के साथ किसी संव्यवहार :

परंतु खंड (ग) के प्रतिषेध में भा.रि.बे. द्वारा, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :—कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची 2 में सम्मिलित किसी संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा नहीं लेगा :

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां संदाय प्रेषक के रेसिडेन्ट फारेन करेंसी (आर एफ सी) खाते या एक्सचेन्ज अर्नर्स फारेन करेंसी (ई ई एफ सी) खाते में धारित निधि से किया जाता है।

5. रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :—कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची 3 में सम्मिलित किसी संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा नहीं लेगा :

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां संदाय प्रेषक के रेसिडेन्ट फारेन करेंसी (आर एफ सी) खाते या एक्सचेन्ज अर्नर्स फारेन करेंसी (ई ई एफ सी) खाते में धारित निधि से किया जाता है।

अनुसूची-1

[नियम 3 देखिए]

चालू खाते के ऐसे संव्यवहारों की सूची जिसके लिए विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय प्रतिषिद्ध है

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण।
2. घुड़दौड़/घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरूचि से उत्पन्न आय से प्रेषण।
3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/अभिनिषिद्ध पत्रिका के क्रय के लिए फुटबाल पूल दांव लगाने आदि के लिए प्रेषण।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त वेंचर/संपूर्ण स्वामित्व समनुषंगियों में इक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर दलाली का संदाय।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए शेष लाभांश की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण।
6. रुपए स्टेट क्रेडिट रूप के अधीन निर्यात पर दलाली का संदाय।
7. दूरभाष के "काल बैंक सर्विसेज" से संबंधित संदाय।
8. एन, आर एस आर अनिवासी विशेष रुपए के खाते में रखी निधियों पर ब्याज से आय से प्रेषण।

अनुसूची-2

[नियम 4 देखिए]

चालू खाते के संव्यवहार की सूची जिसके लिए विदेशी मुद्रा के खरीदने से पहले भारत सरकार से अनुमोदन अपेक्षित है

प्रेषण का प्रयोजन

अनुमोदन

भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका

अपेक्षित है

1. सांस्कृतिक टयूर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा और संस्कृति विभाग)

2. किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम/राज्य और केन्द्रीय सरकार विभाग द्वारा विदेश में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
3. पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिया गया जलयान के माल भाड़े से प्रेषण	जल भूतल मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सी आई एफ पर आधारित (जैसे एफ. ओ. बी. और एफ. ए. एस. पर आधारित को छोड़कर) पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा आयात पर संदाय	जल भूतल मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहु मोडल परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
6. ट्रांसपोंडरों के भाड़ा प्रभागों का प्रेषण	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
7. पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विहित आधान निरोध प्रभार से अधिक दर का प्रेषण।	जल भूतल मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का संदाय स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का संदाय 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
9. यदि अंतर्वर्तित रकम 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक है तब अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रिया कलाओं के प्राइज धन/प्रयोजन का प्रेषण।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग)
10. विदेशी कंपनी से स्वास्थ्य के लिए बीमा सुनिश्चित करने के लिए संदाय।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची 3

(नियम 5 देखिए)

1. कलाकार जैसे कुश्तीबाज, नाचने वाला, मनोरंजन करने वाला आदि द्वारा प्रेषण (यह निर्बंधन ऐसे कलाकारों पर लागू नहीं है जो विशेष उत्सव के दौरान भारत में पर्यटक संबंधी संगठनों जैसे आई टी डी सी, राज्य पर्यटन विकास निगम आदि द्वारा नियुक्त किए गए हों या वे कलाकार जो पांच सितारा प्रवर्गों के होटलों द्वारा नियुक्त किए गए हों, परन्तु व्यय ई ई एफ सी खातों से किया जाता है)।

2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक निजी यात्रा के लिए एक कलेंडर वर्ष में 5,000 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा को निकालना।

3. 5,000 अमरीकी डालर प्रति हिताधिकारी प्रति वर्ष से अधिक दान का प्रेषण।

4. 5,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष प्रति हिताधिकारी से अधिक संदान।

5. रोजगार के लिए विदेश में गए व्यक्तियों के लिए 5,000 अमरीकी डालर से अधिक मुद्रा सुविधाएं।

6. 5,000 अमरीकी डालर से अधिक या देश में उत्प्रवास के लिए उसके द्वारा विहित रकम उत्प्रवास के लिए मुद्रा सुविधाएं।

7. विदेश में रह रहे नजदीकी संबंधियों के भरण-पोषण के लिए 5,000 अमरीकी डालर से अधिक प्रति वर्ष प्रत्येक प्राप्तिकर्ता का प्रेषण।

8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि को विचार में न लाते हुए, कारबार यात्रा के लिए या किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए या विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने के लिए या विदेश में जांच पड़ताल कराने के लिए या चिकित्सीय उपचार/जांच पड़ताल के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए 25,000 अमरीकी डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना।

9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी हस्पताल/चिकित्सक द्वारा प्राक्कलन से अधिक मुद्रा जारी करना।

10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के प्राक्कलनों से अधिक या 30,000 अमरीकी डालर जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में रहने के लिए फ्लेटों/वाणिज्यिक प्लेटों के विक्रय के लिए 5 प्रतिशत से अधिक आवक प्रेषण के लिए विदेश से अभिकर्ता को कमीशन।

12. भारतीय कंपनियों के विदेशी कार्यालयों को अल्पकालीन प्रत्यय।

13. किसी व्यक्ति द्वारा, जिसकी निर्यात से अर्जित आय प्रत्येक पिछले दो वर्षों के दौरान 10 लाख से कम है, विदेशी टेलीविजन पर विज्ञापन के लिए प्रेषण।

14. तकनीकी सहयोगी करार, जो रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, के अधीन स्यामित्व और एक मुश्त फीस के संदाय का प्रेषण।

15. विदेश से उपाप्त की गई स्थापत्य परामर्शी सेवाओं के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक प्रेषण।

16. भारत में व्यापार चिन्ह/विशेषाधिकार के उपयोग और/या क्रय करने के लिए प्रेषण।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

राम सेवक शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2000

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, and in consultation with the Reserve Bank, the Central Government having considered it necessary in the public interest, makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000;

(2) They shall come into effect on the 1st day of June, 2000.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (b) “Drawal” means drawal of foreign exchange from an authorised person and includes opening of Letter of Credit or use of International Credit Card or International Debit Card or ATM Card or any other thing by whatever name called which has the effect of creating foreign exchange liability;
- (c) “Schedule” means a schedule appended to these rules;
- (d) The words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on drawal of Foreign Exchange.—Drawal of foreign exchange by any person for the following purpose is prohibited, namely :

- (a) a transaction specified in the Schedule I; or
- (b) a travel to Nepal and/or Bhutan; or
- (c) a transaction with a person resident in Nepal or Bhutan :

Provided that the prohibition in clause (c) may be exempted by RBI subject to such term and conditions as it may consider necessary to stipulate by special or general order.

4. Prior approval of Govt. of India.—No person shall draw foreign exchange for a transaction included in the Schedule II without prior approval of the Government of India :

Provided that this Rule shall not apply where the payment is made out of funds held in Resident Foreign Currency (RFC) Account or Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account of the remitter.

5. Prior approval of Reserve Bank.

No person shall draw foreign exchange for a transaction included in the Schedule III without prior approval of the Reserve Bank;

Provided that this Rule shall not apply where the payment is made out of funds held in Resident Foreign Currency (RFC) Account or Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account of the remitter.

Schedule I

(See Rule 3)

1. Remittance out of lottery winnings.
2. Remittance of income from racing/riding etc. or any other hobby,
3. Remittance for purchase of lottery tickets, banned/prescribed magazines, football pools, sweepstakes etc.
4. Payment of commission on exports made towards equity investment in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries abroad of Indian companies,
5. Remittance of dividend by any company to which the requirement of dividend balancing is applicable,
6. Payment of commission on exports under Rupee State Credit Route,
7. Payment related to "Call Back Services" of telephones,
8. Remittance of interest income on funds held in Non-Resident Special Rupee Scheme a/c.

Schedule II

(See Rule 4)

Purpose of Remittance**Ministry/Department of Govt. of India whose approval is required**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cultural Tours. | Ministry of Human Resources Development, (Department of Education and Culture) |
| 2. Advertisement abroad by any PSU/State and Central Government Department | Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) |
| 3. Remittance of freight of vessel chartered by a PSU | Ministry of Surface Transport, (Chartering Wing) |
| 4. Payment of import by a Govt. Department or a PSU on c.i.f. basis (i.e. other than f.o.b and f.a.s. basis) | Ministry of Surface Transport, (Chartering Wing) |
| 5. Multi-modal transport operators making remittance to their agents abroad | Registration Certificate from the Director General of Shipping |
| 6. Remittance of hiring charges of transponders | Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs). |
| 7. Remittance of container detention charges exceeding the rate prescribed by Director General of Shipping. | Ministry of Surface Transport (Director General of Shipping) |
| 8. Remittances under technical collaboration agreements where payment of royalty exceeds 5% on local sales and 8% on exports and lump-sum payment exceeds US\$ 2 million. | Ministry of Industry and Commerce, |

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Remittance of prize money/sponsorship of sports activity abroad by a person other than International/National/State Level sports bodies, if the amount involved exceeds US\$ 100,000 | Ministry of Human Resource Development, (Department of Youth Affairs and Sports), |
| 10. | Payment for securing Insurance for health from a company abroad, | Ministry of Finance, (Insurance Division) |
| 11. | Remittance for membership of P & I Club | Ministry of Finance, (Insurance Division) |

Schedule III

(See Rule 5)

1. Remittance by artiste e.g. wrestler, dancer, entertainer etc. (This restriction is not applicable to artistes engaged by tourism related organisations in India like ITDC, State Tourism Development Corporations etc. during special festivals or those artistes engaged by hotels in five star categories, provided the expenditure is met out of EEFC account.)
2. Release of exchange exceeding US\$ 5,000 or its equivalent in one calendar year, for one or more private visits to any country (except Nepal and Bhutan),
3. Gift remittance exceeding US\$ 5,000 per beneficiary per annum,
4. Donation exceeding US\$ 5,000 per annum per beneficiary,
5. Exchange facilities exceeding US\$ 5000 for persons going abroad for employment.
6. Exchange facilities for emigration exceeding US\$ 5,000 or amount prescribed by country of emigration.
7. Remittance for maintenance of close relatives abroad exceeding US\$ 5,000 per year per recipient,
8. Release of foreign exchange, exceeding US\$ 25,000 to a person, irrespective of period of stay, for business travel, or attending a Conference or specialised training or for maintenance expenses of a patient going abroad for medical treatment or check-up abroad, or for accompanying as attendant to a patient going abroad for medical treatment/Check-up.
9. Release of exchange for meeting expenses for medical treatment abroad exceeding the estimate from the doctor in India or hospital/doctor abroad.
10. Release of exchange for studies abroad exceeding the estimates from the institution abroad or US\$ 30,000, whichever is higher.
11. Commission to agents abroad for sale of residential flats/commercial plots in India, exceeding 5% of the inward remittance.
12. Short term credit to overseas offices of Indian companies.
13. Remittance for advertisement on foreign television by a person whose export earnings are less than Rs. 10 lakhs during each of the preceding two years.
14. Remittances of royalty and payment of lump-sum fee under the technical collaboration agreement which has not been registered with Reserve Bank.
15. Remittances exceeding US\$ 100,000 for architectural/consultancy services procured from abroad.
16. Remittances for use and/or purchase of trade mark/franchise in India.

[F. No. 1/9/EC/97]

R.S. SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा.का.नि. 382 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 16 की उपधारा (1), धारा 17 की उपधारा (3) और धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए जांच करने के लिए और उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन अपीलों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (न्यायनिर्णायक कार्यवाहियां और अपील) नियम, 2000 है।

(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) “आवेदक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यथास्थिति, विशेष निदेशक (अपील) या अपील अधिकरण के समक्ष अपील की है;

(घ) “अपील अधिकरण” से अधिनियम की धारा 18 के अधीन स्थापित विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) “विशेष निदेशक (अपील)” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक (अपील) अभिप्रेत है;

(ज) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उस अधिनियम में हैं।

3. **न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति**—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के उतने अधिकारी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे।

4. **जांच किया जाना** : (1) अधिनियम की धारा 13 के अधीन न्यायनिर्णयन के उस प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम की उस धारा में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए (जो उसकी तारीख की तारीख से दस दिन से कम न हो), यह कारण दर्शित करने के लिए कि उसके विरुद्ध क्यों न जांच की जाए, एक सूचना भेजेगा।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, उसके द्वारा अभिकथित रूप से कारित उल्लंघन की प्रकृति उपदर्शित करेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात् यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से जो उसके द्वारा किया गया है, उपस्थित होने के लिए एक तारीख नियत करते हुए, एक सूचना भेजेगा।

(4) नियत की गई तारीख पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है या उसके विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अधिनियम या नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश या आदेश के उपबंधों को उपदर्शित करते हुए या कोई ऐसी शर्त को जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई प्राधिकार जारी किया गया है जिसके संबंध में उल्लंघन किया जाना अभिकथित है, स्पष्ट करेगा कि उक्त उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है।

(5) उसके पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझता है, प्रस्तुत करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को भावी तारीख के लिए स्थगित करेगा और ऐसा साक्ष्य लेने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

(6) इस नियम के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, साक्ष्य देने या किसी ऐसे दस्तावेज को जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, पेश करने के लिए समन करे और हाजिर कराए।

(7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) की अपेक्षानुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है उपेक्षा या इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियां कर सकेगा।

(8) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति, जिसे वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(9) नियम 4 के उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अधिनियम या नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश या आदेश के उपबंध या किसी ऐसी शर्त को जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसे विनिश्चय के लिए संक्षिप्त कारणों को अन्तर्विष्ट करेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित होगा।

(11) नियम 4 के उपनियम (8) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है और कार्यवाहियों की अन्य सभी प्रतियां उसे दो रुपया प्रति पृष्ठ की दर से प्रतिलिपि फीस के संदाय पर दी जाएगी।

(12) उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्रतिलिपि फीस का संदाय नकद या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा।

विशेष निदेशक (अपील) को अपील

5. अपील का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 17 के अधीन विशेष निदेशक (अपील) को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील प्ररूप 1 में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। अपील तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीन प्रतियां संलग्न होंगी। प्रत्येक अपील के साथ नकद रूप में पांच हजार रुपए या विशेष निदेशक (अपील) के पक्ष में पांच हजार रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न करेगा।

(2) अपील संक्षिप्त रूप में होगी और बिना वर्णनात्मक तर्कों के अपील किए गए आदेश के आक्षेप के आधार विभिन्न शीर्षों में होंगे और ऐसे आधार क्रमशः संख्यांकित होंगे क्या तामील के लिए वह पता जिस पर सूचना या अन्य आदेशिकाएं आवेदक को तामील की जाएंगी, वह तारीख जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आवेदक को तामील किया गया था, विनिर्दिष्ट होगी।

(3) जहां अपील धारा 17 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, वहां इसके साथ एक अर्जी सम्यक् रूप से सत्यापित और दस्तावेजों से समर्थित, यदि कोई है, जिनका आवेदक द्वारा अवलम्ब लिया गया है, तीन प्रतियों में यह कारण दर्शित करते हुए संलग्न होंगी कि आवेदक को उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित किया गया था।

(4) प्रत्येक सूचना जिसकी आवेदक पर तामील की जानी अपेक्षित है, उसको अपील में विनिर्दिष्ट तामील के लिए पते पर, नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में, तामील की जाएगी।

6. विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष प्रक्रिया

(1) नियम 5 के अधीन अपील की प्राप्ति पर, विशेष निदेशक (अपील) अपील की एक प्रति उस आदेश की एक प्रति के साथ जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रवर्तन निदेशक को भेजेगा।

(2) तत्पश्चात्, विशेष निदेशक (अपील) अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करते हुए आवेदक और प्रवर्तन निदेशक को सूचनाएं जारी करेगा।

(3) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक और प्रवर्तन निदेशालय के उपस्थापन अधिकारी को सुना जाएगा।

(4) जहां नियत तारीख को या किसी अन्य दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक या उपस्थापन अधिकारी अपील सुनवाई पर उपस्थित होने में असफल रहता है जब विशेष निदेशक (अपील) अपील को मामले के गुणागुण पर विनिश्चित कर सकेगा।

7. अपील में किए गए आदेश की विषय वस्तु—(1) विशेष निदेशक (अपील) का आदेश लिखित रूप में होगा और इसमें विनिश्चय के आधारों का संक्षिप्त उल्लेख होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश अपील की सुनवाई करने वाले विशेष निदेशक (अपील) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

8. पक्षकार का अभ्यावेदन—कोई आवेदक, जिसने अधिनियम की धारा 17 के अधीन विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष अपील फाइल की है, अधिनियम के अधीन विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए और अभिवचन करने के लिए विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त कर सकेगा।

9. सूचनाओं, अध्यक्षों या आदेशों की तामील—इन नियमों के अधीन जारी कोई सूचना, अध्यक्ष या कोई आदेश किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित रीति में तामील किया जा सकेगा अर्थात्,

- (क) उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को सूचना या अध्यक्ष या आदेश के परिदान या निविदा द्वारा,
- (ख) उसे अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर जहां वह कारबार कर रहा है या अन्तिम बार कर रहा था या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य कर रहा है या अन्तिम समय तक कार्य कर रहा था, सूचना या अध्यक्ष या आदेश भेजकर, या
- (ग) ऐसे परिसर के बाहर के दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग में, जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अन्तिम ज्ञात निवास कर रहा था कारबार कर रहा था या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है या अन्तिम बार कार्य कर रहा था, चिपका कर और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई होनी चाहिए ; या
- (घ) यदि सूचना या अध्यक्ष या आदेश खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन तामील नहीं किए जा सकते तो इसे मुख्य समाचारपत्र में (जनभाषा और अंग्रेजी दोनों में), जिनका उस क्षेत्र या अधिकारिता में विस्तृत परिचालन हो जहां वह व्यक्ति निवास करता है या उसका अन्तिम ज्ञात निवास रहा है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अन्तिम बार कार्य कर रहा था, प्रकाशित करके।

अपील अधिकरण को अपील

10. अपील का प्ररूप—(1) अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील अधिकरण को की गई प्रत्येक अपील आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 2 में होगी। अपील तीन प्रतियों में भेजी जाएगी और इसके साथ उस आदेश की तीन प्रतियां संलग्न होंगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। प्रत्येक अपील के साथ दस हजार रुपए की फीस नकद रूप में या रजिस्ट्रार विदेशी मुद्रा, अपील अधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होगी:

परन्तु आवेदक यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम ऐसे प्राधिकारी को निक्षेपित कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 19 के पहले परन्तुक के अधीन अधिसूचित किया जाए :

परन्तु यह और कि जहां किसी विशिष्ट मामले में अपील अधिकरण की यह राय है कि ऐसी शास्ति का निक्षेप ऐसे व्यक्ति को असम्यक् कठिनाई पारित करेगा वहां अपील अधिकरण शास्ति की वसूली सुरक्षित करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे जिससे कि ऐसे निक्षेप से उसे अभिमुक्त कर सकेगा।

(2) अपील में संक्षिप्त रूप में और विभिन्न शीर्षों के अधीन उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आक्षेप के आधारों को बिना किसी वर्णनात्मक तर्क के लिखा जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमशः संख्यांकित किया जाएगा तथा तामील के लिए वह पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर आवेदक के लिए सूचना या अन्य आदेशिकाएं तामील की जाएंगी, वह तारीख जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है आवेदक पर तामील किया गया था और धारा 13 के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित राशि तथा उप-नियम (1) में विहित फीस की रकम जो जमा कर दी गई है या नहीं, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) जहां अपील धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की गई है वहां यह तीन प्रतियों में एक अर्जी के साथ जो सम्यक् रूप से सत्यापित की गई हो और दस्तावेजों द्वारा, यदि कोई हों, जिनका आवेदक द्वारा अवलम्ब लिया गया है, समर्थित हो, संलग्न होगी, यह दर्शित किया जाएगा कि किस प्रकार आवेदक को उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित किया गया था।

(4) आवेदक पर तामील की जाने वाली अपेक्षित कोई सूचना अपील में विनिर्दिष्ट तामील के पते पर नियम 14 में विहित रीति में, उसे तामील की जाएगी।

11. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया—(1) नियम 10 के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर अपील अधिकरण, अपील की एक प्रति उस आदेश की एक प्रति के साथ जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रवर्तन निदेशक को भेजेगा।

(2) अपील अधिकरण, तत्पश्चात्, अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करते हुए आवेदक और प्रवर्तन निदेशक को सूचनाएं जारी करेगा।

(3) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक और प्रवर्तन निदेशालय के उपस्थापन अधिकारी को सुना जाएगा।

(4) जहां नियत तारीख को या किसी ऐसे दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक या उपस्थापन अधिकारी अपील की सुनवाई पर उपस्थित होने में असफल रहता है जब तो अपील अधिकरण अपील को मामले के गुणागुण पर विनिश्चित कर सकेगा।

12. अपील में आदेश की विषयवस्तु—(1) अपील अधिकरण का आदेश लिखित में होगा और विनिश्चय के लिए आधारों का संक्षिप्त उल्लेख होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश पर अपील की सुनवाई करने वाले अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

13. **पक्षकार का अभ्यावेदन**—कोई आवेदक जिसने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की है, अधिनियम के अधीन विशेष निदेशक (अपील) के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए और अभिवचन तथा कार्य करने के लिए विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त कर सकेगा।

14. **सूचनाओं, अध्यपेक्षाओं या आदेश की तामील**—इन नियमों के अधीन जारी कोई सूचना, अध्यपेक्षा या कोई आदेश किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित रीति में तामील किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश के परिदान या निविदा द्वारा,
- (ख) उसे अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर जहां वह कारबार कर रहा है या अन्तिम बार कर रहा था या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है या अन्तिम बार कार्य कर रहा था, सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश भेजकर, या
- (ग) ऐसे परिसर के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग में, जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अन्तिम ज्ञात निवास कर रहा था या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अन्तिम बार कार्य कर रहा था, चिपका कर और उसकी लिखित रिपोर्ट दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई होनी चाहिए, या
- (घ) यदि सूचना या अध्यपेक्षा या आदेश खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन तामील नहीं किया जा सकता तो ऐसे मुख्य समाचार पत्र में (जनभाषा और अंग्रेजी दोनों में) प्रकाशित करके जिनका उस क्षेत्र में या उसका अधिकारिता में जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अन्तिम बार निवास किया गया ज्ञात है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अन्तिम बार कार्य कर रहा था, वृहत परिचालन है।

[फा० सं० 1/9/ई सी/97]

राम सेवक शर्मा, संयुक्त सचिव

प्रारूप 1

(नियम 5 देखिए)

अपील का प्रारूप

ओर से

(यहां आवेदक का नाम और पता लिखें)

सेवा में,

विशेष निदेशक (अपील)

(पता)

महोदय,

ऊपर नामित आवेदक, विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश सं०..... तारीख..... के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह अपील करने का निवेदन करता है।

तथ्य

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्त में उल्लेख करें। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रतियां संलग्न करें।)

आधार

(यहाँ उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)

प्रार्थना

ऊपरलिखित को ध्यान में रखते हुए, आवेदक प्रार्थना करता है कि उसे निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया जाए।

ईप्शित अनुतोष

(ईप्शित अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

इस अपील के लिए रुपए की फीस
 में रसीद संख्यांक तारीख

द्वारा निक्षेपित कर दी गई है।

स्थान

तारीख

(आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

संलग्न दस्तावेजों की सूची :

(आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

प्रारूप-2

(नियम 10 देखिए)

अपील का प्रारूप

ओर से

(यहां आवेदक का नाम और पता लिखें)

सेवा में,

रजिस्ट्रार

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण

(पता)

महोदय,

ऊपर नामित आवेदक, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश सं० तारीख के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर यह अपील करने का निवेदन करता है।

तथ्य

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्त में उल्लेख करें। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई हों, की प्रतियां संलग्न करें।)

आधार

(यहाँ उन आधारों का उल्लेख करें जिन पर अपील की गई है)

प्रार्थना

ऊपरलिखित को ध्यान में रखते हुए, आवेदक प्रार्थना करता है कि उसे निम्नलिखित अनुतोष अनुदत्त किया जाए।

ईप्शित अनुतोष

(ईप्शित अनुतोष विनिर्दिष्ट करें)

1. इस अपील के लिए रुपए की फीस
 में रसीद संख्यांक तारीख द्वारा
 निक्षेपित कर दी गई है।

2. इस अपील के लिए यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम
 रुपए में रसीद सं. तारीख द्वारा निक्षेपित कर दी गई
 है।

स्थान

तारीख :

(आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

संलग्न दस्तावेजों की सूची :

(आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2000

G.S.R. 382(E).— In exercise of the powers conferred by section 46 read with sub-section (1) of section 16, sub-section (3) of section 17 and sub-section (2) of section 19 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules for holding enquiry for the purpose of imposing penalty and appeals under chapter V of the said Act, namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Adjudication Proceedings and Appeal) Rules, 2000.
(2) They shall come into force on the 1st day of June, 2000
2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
 - (b) "Adjudicating Authority" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 16 of the Act;
 - (c) "applicant" means an aggrieved person who makes an appeal before Special Director (Appeals) or Appellate Tribunal, as the case may be.
 - (d) "Appellate Tribunal" means the Appellate Tribunal for Foreign Exchange established under section 18 of the Act;
 - (e) "Form" means form appended to these rules;
 - (f) "Section" means a section of the Act;
 - (g) "Special Director (Appeals)" means Special Director (Appeals) appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 17 of the Act;
 - (h) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. **Appointment of Adjudicating Authority**, - The Central Government may, by an order published in the official Gazette, appoint as many officers of the Central Government as it may think fit, as the Adjudicating Authorities for holding inquiry under the provisions of chapter IV of the Act.

4. **Holding of inquiry** (1) For the purpose of adjudicating under section 13 of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section of the Act, the Adjudicating Authority shall, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than ten days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
- (2) Every notice under sub-rule (1) to any such person shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed by him.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the Adjudicating Authority is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his legal practitioner or a chartered accountant duly authorised by him.
- (4) On the date fixed, the Adjudicating Authority shall explain to the person proceeded against or his legal practitioner or the chartered accountant, as the case may be, the contravention, alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act or of rules, regulations, notifications, direction or orders or any condition subject to which an authorisation is issued by the Reserve Bank of India in respect of which contravention is alleged to have taken place.
- (5) The Adjudicating Authority shall, then, given an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the Adjudicating Authority shall not be bound to observe the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).
- (6) While holding an inquiry under this rule the Adjudicating Authority shall have the power to summon and enforce attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Adjudicating Authority may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (3) before the Adjudicating Authority, the Adjudicating Authority may proceed with the adjudication proceedings in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Authority, the Adjudicating Authority is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of section 13 of the Act.
- (9) Every order made under sub-rule (8) of the rule 4 shall specify the provisions of the Act or of the rules, regulations, notifications, direction or orders or any condition subject to which an authorisation is issued by the Reserve Bank of India in respect of which contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decisions.
- (10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the Adjudicating Authority.
- (11) A copy of the order made under sub-rule (8) of rule 4 shall be supplied free of charge to the person against whom the order is made and all other copies of proceedings shall be supplied to him on payment of copying fee @ Rs. 2 per page.
- (12) The copying fee referred to in sub-rule (11) shall be paid in cash or in the form of demand draft in favour of the Adjudicating Authority.

Appeal to Special Director (Appeal)

5. Form of appeal - (1) Every appeal presented to the Special Director (Appeals) under section 17 of the Act shall be in the Form I signed by the applicant. The appeal shall be filed in triplicate and accompanied by three copies of the order appealed against. Every appeal shall be accompanied by a fee of Rupees five thousand in the form of cash or demand draft payable in favour of the Special Director (Appeal).

(2) The appeal shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the order appealed against without any argument of narrative and such grounds shall be numbered consecutively; and shall specify the address for service at which notice or other processes may be served on the applicant, the date on which the order appealed against was served on the applicant.

(3) Where the appeal is presented after the expiry of the period of forty five days referred to in sub-section (3) of section 17, it shall be accompanied by a petition, in triplicate, duly verified and supported by the documents, if any, relied upon by the applicant, showing cause how the

applicant had been prevented from preferring the appeal within the said period of forty five days.

(4) Any notice required to be served on the applicant shall be served on him in the manner specified in rule 9 at the address for service specified in the appeal.

6. Procedure before Special Director (Appeals) - (1) On receipt of an appeal under rule 5, the Special Director (Appeals) shall send a copy of the appeal, together with a copy of the order appealed against, to the Director of Enforcement.

(2) The Special Director (Appeals) shall, then, issue notices to the applicant and the Director of Enforcement fixing a date for hearing of the appeal.

(3) On the date fixed for hearing of the appeal or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, the applicant as well as the presenting officer of the Directorate of Enforcement shall be heard.

(4) Where on the date fixed, or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, the applicant or the presenting officer fail to appear when the appeal is called for hearing, the Special Director (Appeals) may decide the appeal on the merits of the case.

7. Contents of the Order in appeal- (1) The order of Special Director (Appeals) shall be in writing and shall state briefly the grounds for the decision.

(2) The order referred to in sub-rule (1) shall be signed by the Special Director (Appeal) hearing the appeal.

8. Representation of party - Any applicant who has filed an appeal before the Special Director (Appeals) under section 17 of the Act, may appoint a legal practitioner or a chartered accountant to appear and plead and act on his behalf before the Special Director (Appeal) under the Act.

9. Service of notices, requisitions or orders - A notice, requisition or an order issued under these rules shall be served on any person in the following manner, that is to say,

- (a) by delivering or tendering the notice or requisition or order to that person or his duly authorised person,
- (b) by sending the notice or requisition or order to him by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place or residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain, or
- (c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided

- or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons; or
- (d) if the notice or requisition or order cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), by publishing in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation of area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

Appeal to the Appellate Tribunal

10. Form of appeal - (1) Every appeal presented to the Appellate Tribunal under section 19 of the Act shall be in the Form II signed by the applicant. The appeal shall be sent in triplicate and accompanied by three copies of the order appealed against. Every appeal shall be accompanied by a fee of Rupees ten thousand in the form of cash or demand draft payable in favour of the Registrar, Appellate Tribunal for Foreign Exchange, New Delhi:

Provided that the applicant shall deposit the amount of penalty imposed by the Adjudicating Authority or the Special Director (Appeals) as the case may be, to such authority as may be notified under the first proviso to section 19 of the Act:

Provided further that where in a particular case, the Appellate Tribunal is of the opinion that the deposit of such penalty would cause undue hardship to such person, the Appellate Tribunal may dispense with such deposit subject to such conditions as it may deem fit to impose so as to safeguard the realisation of penalty.

- (2) The appeal shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the order appealed against without any argument of narrative and such grounds shall be numbered consecutively; and shall specify the address for service at which notice or other processes may be served on the applicant, the date on which the order appealed against was served on the applicant; and the sum imposed by way of penalty under section 13 and the amount of fee prescribed in sub-rule (1) had been deposited or not.
- (3) Where the appeal is presented after the expiry of the period of forty five days referred to in sub-section (2) of section 19, it shall be accompanied by a petition, in triplicate, duly verified and supported by the documents, if any, relied upon by the applicant, showing cause how the applicant had been prevented from preferring the appeal within the said period of forty five days.

- (4) Any notice required to be served on the applicant shall be served on him in the manner prescribed in rule 14 at the address for service specified in the appeal.

11. Procedure before Appellate Tribunal - (1) On receipt of an appeal under rule 10, the Appellate Tribunal shall send a copy of the appeal, together with a copy of the order appealed against, to the Director of Enforcement.

(2) The Appellate Tribunal shall, then, issue notices to the applicant and the Director of Enforcement fixing a date for hearing of the appeal.

(3) On the date fixed for hearing of the appeal, or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, the applicant as well as the presenting officer of the Directorate of Enforcement shall be heard.

(4) Where on the date fixed, or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, the applicant or the presenting officer fail to appear when the appeal is called on for hearing, the Appellate Tribunal may decide the appeal on the merits of the case.

12. Contents of the Order in appeal- (1) The order of Appellate Tribunal shall be in writing and shall state briefly the grounds for the decision.

(2) The order referred to in sub-rule (1) shall be signed by the Chairman or Member of the Appellate Tribunal hearing the appeal.

13. Representation of party - Any applicant who has filed an appeal before the Appellate Tribunal under section 19 of the Act may appoint a legal practitioner or a chartered accountant to appear and plead and act on his behalf before the Special Director (Appeal) under the Act.

14 Service of notices, requisitions or orders - A notice, requisition or an order issued under these rules shall be served on any person in the following manner, that is to say,

- (a) by delivering or tendering the notice or requisition or order to that person or his duly authorised person,
- (b) by sending the notice or requisition or order to him by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place or residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain, or
- (c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons; or
- (d) if the notice or requisition or order cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), by publishing in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation of area or

jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

[F. No. 1/9/EC/97]

R. S. SHARMA, Jt. Secy.

FORM-1

(See rule 5)

FORM OF APPEAL

From

(Mention the name and address of the applicant here)

To

The Special Director (Appeals)
(Address)

Sir,

The applicant named above, begs to prefer this appeal under section 17 of the Foreign Exchange Management Act 1999 against order No. _____ dated _____ passed by the Adjudicating Authority under the said Act on the following facts and grounds.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose copy of the order passed by the Adjudicating Authority and copies of other relevant documents, if any)

GROUND

(Mention here the grounds on which the appeal is made)

PRAYER

In the light of what is stated above, the applicant prays that he/she it may be granted the following relief.

RELIEF SOUGHT

(Specify the relief sought)

The fee of Rs _____ for this appeal has been deposited in _____ vide receipt No. _____ dated _____.

Place

Date

(Signature of the applicant
or his Authorised representative)

List of documents attached:

(Signature of the applicant
or his authorised representative)

FORM-II
(See rule 10)

FORM OF APPEAL

From
(Mention the name and address of the applicant here)

To
The Registrar
Appellate Tribunal for Foreign Exchange.
(Address)

Sir,
The applicant named above, begs to prefer this appeal under section 17 of the Foreign Exchange Management Act 1999 against order No. _____ dated _____ passed by the Adjudicating Authority under the said Act on the following facts and grounds.

FACTS

(Mention briefly the facts of the case here. Enclose copy of the order passed by the Adjudicating Authority and copies of other relevant documents, if any)

GROUND

(Mention here the grounds on which the appeal is made)

PRAYER

In the light of what is stated above, the applicant prays that he/she it may be granted the following relief.

RELIEF SOUGHT
(Specify the relief sought)

1. The fee of Rs. _____ for this appeal has been deposited in _____ vide receipt No. _____ dated _____.
2. The amount of penalty imposed by Adjudicating Authority or Special Director (Appeal), as the case may be, Rs. _____ for this appeal has been deposited in _____ vide receipt No. _____ dated _____.

Place
Date

(Signature of the applicant
or his Authorised representative)

List of documents attached:

(Signature of the applicant
or his authorised representative)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा० का० नि० 383(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 15 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन उल्लंघनों के शमन के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाहियां) नियम, 2000 है ।

(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकृत अधिकारी” से नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) “आवेदक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम धारा 15 (1) के अधीन शमन प्राधिकारी को आवेदन करता है ;

(घ) “शमन आदेश” से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त उन सभी शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. (1) “शमन प्राधिकारी” से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत हैं, अर्थात् :-

(क) प्रवर्तन निदेशालय का कोई अधिकारी जो उपनिदेशक या उप विधि सलाहकार (उ.वि.स.) की रैंक से नीचे का न हो ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी जो सहायक महा प्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो ।

4. रिजर्व बैंक की उल्लंघन शमन करने की शक्ति : (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 या सा.का.नि.सं..... द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 की तीसरी अनुसूची के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघनों का शमन—

(क) उस मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में अंतर्वर्तित राशि पांच लाख रुपए या कम है, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महा प्रबंधक द्वारा ;

(ख) उस मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में अंतर्वर्तित राशि पांच लाख रुपए से अधिक किंतु बीस लाख रुपए से कम है, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक द्वारा ;

(ग) उस मामले में जहां उल्लंघन में अंतर्वलित राशि बीस लाख रुपए या अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से कम है, भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबंधक द्वारा ;

(घ) उस मामले में जहां ऐसे उल्लंघन में अंतर्वलित राशि पचास लाख रुपए या अधिक है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा ;

क्रिया जा सकेगा :

परंतु यह कि किसी उल्लंघन का तब तक शमन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे उल्लंघन में अंतर्वलित राशि परिमाणन योग्य न हो ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा, उस तारीख से, जिसको उसके द्वारा किए गए किसी उल्लंघन का इन नियमों के अधीन शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए वैसे ही उल्लंघन पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको पहले किए गए उल्लंघन का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया दूसरा या उत्तरवर्ती उल्लंघन, पहला उल्लंघन समझा जाएगा ।

(3) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी किसी उल्लंघन का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा ।

(4) इस नियम के अधीन किसी उल्लंघन का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन, प्ररूप में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को, शमन प्राधिकारी के पक्ष में 5000 रुपए की फीस के मांगदेय ड्राफ्ट के साथ किया जाएगा ।

5. प्रवर्तन निदेशालय की उल्लंघन शमन करने की शक्ति—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 या सा.का.नि. सं. द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा (चालू खाता संव्यवहार) नियम 2000 की तीसरी अनुसूची से भिन्न धाराओं के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन का शमन—

(क) उस मामले में, जहां ऐसे संव्यवहार में अंतर्वलित राशि पांच लाख रुपए या कम है, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा ;

(ख) उस मामले में, जहां ऐसे उल्लंघन में अंतर्वलित राशि पांच लाख रुपए से अधिक किंतु दस लाख रुपए से कम है, प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक द्वारा ;

(ग) उस मामले में जहां उल्लंघन में अंतर्वलित राशि दस लाख रुपए या अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से कम है, प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक द्वारा ;

(घ) उस मामले में जहां उल्लंघन में अंतर्वलित राशि पचास लाख रुपए या अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से कम है, प्रवर्तन निदेशालय के उप विधि सलाहकार के साथ विशेष निदेशक द्वारा ;

(ङ) उस मामले में, जहां ऐसे उल्लंघन की राशि एक करोड़ रुपए या अधिक है, प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक के साथ प्रवर्तन निदेशक द्वारा ;

क्रिया जा सकेगा :

परंतु यह कि किसी उल्लंघन का तब तक शमन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे उल्लंघन में अंतर्वलित राशि परिमाणन योग्य न हो ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा, उस तारीख से जिसको उसके द्वारा किए गए किसी उल्लंघन का इन नियमों के अधीन शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए वैसे ही उल्लंघन पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको पहले किए गए उल्लंघन का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या उत्तरवर्ती उल्लंघन पहला उल्लंघन समझा जाएगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रवर्तन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी, किसी उल्लंघन को शमन करने की शक्तियों का प्रयोग, प्रवर्तन निदेशक के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(4) इस नियम के अधीन किसी उल्लंघन का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन, प्ररूप में, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को, शमन प्राधिकारी के पक्ष में 5000 रुपए की फीस के मांगदेय ड्राफ्ट के साथ किया जाएगा।

6. जहां किसी उल्लंघन का धारा 16 के अधीन किसी उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के पहले शमन किया गया है, वहां ऐसे उल्लंघन के संबंध में ऐसे उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके संबंध में उल्लंघन का इस प्रकार शमन किया गया है, जांच नहीं की जाएगी।

7. जहां किसी उल्लंघन का शमन धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां नियम 4 या नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे शमन की लिखित में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की सूचना में लाएगा और उल्लंघन के ऐसे शमन की सूचना दिए जाने पर, ऐसे व्यक्ति को जिसके संबंध में उल्लंघन का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित किया जाएगा।

8. शमन के लिए प्रक्रिया— (1) शमन प्राधिकारी, शमन प्रक्रियाओं से सुसंगत किसी जानकारी, अभिलेख या अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकेगा।

(2) शमन प्राधिकारी, यथा संभव शीघ्र और आवेदन की तारीख से 180 दिन के अपश्चात्, सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् शमन आदेश पारित करेगा।

9. शमन की गई राशि का संदाय— जहां किसी उल्लंघन का नियम 8(2) के अधीन शमन किया गया है, वहां ऐसे उल्लंघन में अंतर्वर्तित राशि, ऐसे उल्लंघन के शमन आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, शमन प्राधिकारी के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जाएगी।

10. ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति, नियम 9 के अनुसरण में, उस नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमन की गई राशि का संदाय करने में असमर्थ रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने इन नियमों के अधीन किसी उल्लंघन के शमन के लिए आवेदन कभी किया ही नहीं और उस पर उल्लंघन के लिए अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

11. यदि अधिनियम की धारा 17 या धारा 19 के अधीन अपील फाइल की गई है, तो किसी उल्लंघन का शमन नहीं किया जाएगा।

12. शमन प्राधिकारी के आदेश की अंतर्वस्तु—

(1) प्रत्येक आदेश में अभिकथित उल्लंघन के व्यौरों के साथ अधिनियम या नियम के ऐसे उपबंध या उनके अधीन किए गए ऐसे निदेश, अध्यक्ष, आदेश, जिनकी बाबत उल्लंघन हुआ है, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) ऐसे प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी और शमन प्राधिकारी अपनी मुद्रा सहित हस्ताक्षर करेगा।

13. आदेश की प्रति

नियम 8(2) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, आवेदक और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दी जाएगी।

[फा० सं० 1/9/ई सी/97]

राम सेवक शर्मा, संयुक्त सचिव

प्ररूप

(नियम 4 और 5 देखें)

(दो प्रति में भरे जाने के लिए और इसके साथ जारी किए गए ज्ञापन की प्रमाणित प्रति भी लगी होगी)

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. क्या आवेदक भारत का निवासी है अथवा भारत से बाहर रहता है [कृपया अधिनियम की धारा 2 (v) को निर्दिष्ट करें] :
4. ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का नाम, जिसके समक्ष मामला लंबित है :
5. उत्लंघन की प्रकृति (धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार) :
6. मामले के तथ्य संक्षेप में :
7. शमन के आवेदन के लिए फीस के ब्यौरे :
8. मामले से सुसंगत अन्य कोई जानकारी :

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं / हम, मेरे / हमारे मामले के संबंध में शमन प्राधिकारी का कोई निदेश / आदेश स्वीकार करने को इच्छुक हूं / हैं।

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2000

G.S.R. 383(E).— In exercise of the powers conferred by section 46 read with sub-section (1) of section 15 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Central Government hereby makes the following rules relating to compounding contraventions under chapter IV of the said Act, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules 2000.

(2) They shall come into force on the 1st day of June, 2000

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) "authorised officer" means an officer authorised under sub-rule (1) of rule 3;

(c) "applicant" means a person who makes an application under section 15 (1) of the Act to the compounding authority;

(d) "Compounding Order" means an order issued under sub-section (1) of Section 15 of the Act;

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "section" means a section of the Act;

(g) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3 (1). "Compounding Authority" means the persons authorised by the Central Government under sub-section (1) of section 15 of the Act, namely;

(a) an officer of the Enforcement Directorate not below the rank of Deputy Director or Deputy Legal Adviser, (DLA).

(b) An officer of the Reserve Bank of India not below the rank of the Assistant General Manager.

4. Power of Reserve Bank to compound contravention : (1) If any person contravenes any of the provisions of section 7, or section 8 or section 9 or Third Schedule to the Foreign Exchange (Current Account Transaction) Rules, 2000 notified by GSR No....., such contraventions may be compounded :-

- (a) in case where the sum involved in such contravention is five lakhs rupees or below, by the Assistant General Manager of the Reserve Bank of India ;
- (b) in case where the sum involved in such contravention is more than rupees five lakhs but less than rupees twenty lakhs, by the Deputy General Manager of Reserve Bank of India ;
- (c) in case where the sum involved in the contravention is rupees twenty lakhs or more but less than rupees fifty lakhs by the General Manager of Reserve Bank of India :
- (d) in case the sum involved in such contravention is rupees fifty lakhs or more, by the Chief General Manager of the Reserve Bank of India:

Provided further that no contravention shall be compounded unless the amount involved in such contravention is quantifiable.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to a contravention committed by any person within a period of three years from the date on which a similar contravention committed by him was compounded under these rules.

Explanation :- For the purposes of this rule, any second or subsequent contravention committed after the expiry of a period of three years from the date on which the contravention was previously compounded shall be deemed to be a first contravention.

(3) Every officer specified under sub-rule (1) of rule 4 of the Reserve Bank of India shall exercise the powers to compound any contravention subject to the direction, control and supervision of the Governor of the Reserve Bank of India.

(4) Every application for compounding any contravention under this rule shall be made in Form to the Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Central Office, Mumbai along with a fee of Rs. 5000/- by Demand Draft in favour of compounding authority.

5. The Power of Enforcement Directorate to compound contraventions :- (1) If any person contravenes any of the provisions of sections other than section 7 or section 8 or section 9 or Third Schedule to the Foreign Exchange (Current Account Transaction) Rules, 2000 notified vide GSR No.....such contravention may be compounded :

- (a) in case where the sum involved in such contravention is five lakhs rupees or below, by the Deputy Director of the Directorate of Enforcement;
- (b) in case where the sum involved in such contravention is more than rupees five lakhs but less than rupees ten lakhs, by the Additional Director of the Directorate of Enforcement;
- (c) in case where the sum involved in the contravention is rupees ten lakhs or more but less than fifty lakhs rupees by the Special Director of the Directorate of Enforcement;
- (d) in case where the sum involved in the contravention is rupees fifty lakhs or more but less than one crore rupees by Special Director with Deputy Legal Adviser of the Directorate of Enforcement;
- (e) in case the sum involved in such contravention is one crore rupees or more, by the Director of Enforcement with Special Director of the Enforcement Directorate.

Provided further that no contravention shall be compounded unless the amount involved in such contravention is quantifiable.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to a contravention committed by any person within a period of three years from the date on which a similar contravention committed by him was compounded under these rules.

Explanation :- For the purposes of this rule, any second or subsequent contravention committed after the expiry of a period of three years from the date on which the contravention was previously compounded shall be deemed to be a first contravention.

(3) Every officer of the Directorate of Enforcement specified under sub-rule (1) of this rule shall exercise the powers to compound any contravention subject to the direction, control and supervision of the Director of Enforcement.

(4) Every application for compounding any contravention under this rule shall be made in Form to the Director, Directorate of Enforcement,

New Delhi, along with a fee of Rs.5000 by DD in favour of the Compounding Authority.

6. Where any contravention is compounded before the adjudication of any contravention under section 16, no inquiry shall be held for adjudication of such contravention in relation to such contravention against the person in relation to whom the contravention is so compounded.

7. Where the compounding of any contravention is made after making of a complaint under sub-section (3) of section 16, such compounding shall be brought by the authority specified in rule 4 or rule 5 in writing, to the notice of the Adjudicating Authority and on such notice of the compounding of the contravention being given, the person in relation to whom the contravention is so compounded shall be discharged.

8. **Procedure for Compounding:** (1) The Compounding Authority may call for any information, record or any other documents relevant to the compounding proceedings.

(2) The Compounding Authority shall pass an order of compounding after affording an opportunity of being heard to all the concerned as expeditiously as possible and not later than 180 days from the date of application.

9. **Payment of amount compounded :-** Where a contravention has been compounded under rule 8(2) the sum involved in such contravention shall be deposited within fifteen days from the date of the order of compounding of such contravention by demand draft in favour of the Compounding Authority.

10. In case a person fails to pay the sum compounded in accordance with the rule 9 within the time specified in that rule, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any contravention under these rules and the provisions of the Act for contravention shall apply to him.

11. No contravention shall be compounded if an appeal has been filed under section 17 or section 19 of the Act.

12. **Contents of the order of the Compounding Authority –**

(1) Every order shall specify the provisions of the Act or of the rules, directions, requisitions or orders made thereunder in respect of which contravention has taken place alongwith details of the alleged contravention.

- (2) Every such order shall be dated and signed by the Compounding Authority under his seal.

13. copy of the order.

One copy of the order made under rule 8(2) shall be supplied to the applicant and the Adjudicating Authority as the case may be.

[F. No. 1/9/EC/97]

R. S. SHARMA, Jt. Secy.

FORM

(See Rule 4 or 5)

(To be filed in duplicate and shall be accompanied by certified copy of the Memorandum issued)

1. Name of the applicant:
(In block letters)
2. Full address of the applicant:
3. Whether the applicant is resident in India or resident outside India
[Please refer to section 2(v) of the Act]:
4. Name of the Adjudicating Authority before whom the case is pending:
5. Nature of the contravention (according to sub-section (1) of section 13:
6. Brief facts of the case:
7. Details of fee for application of compounding :
8. Any other information relevant to the case:

I/we declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that I/We am/are willing to accept any direction/order of the Compounding Authority in connection with compounding of my/our case.

DATED

(SIGNATURE OF APPLICANT)